

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
लोक सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या: 900

05 फरवरी, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

बुजुग आबादी का मानसिक स्वास्थ्य

900. प्रो.अच्युतानंद सामंत:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह विदित है कि भारत में बुजुग आबादी का एक बड़ा प्रतिशत भारत में नवीनतम लांगीट्यूडीनल एजिंग स्टडी (एलएएसआई) की रिपोर्ट के अनुसार संभावित गंभीर अवसाद तथा बिगड़ते मानसिक स्वास्थ्य से ग्रसित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार बुजुग आबादी को उनके मानसिक स्वास्थ्य का बेहतर प्रबंधन करने में मदद करने के लिए कदम उठाने पर विचार कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में बढ़ते मानसिक स्वास्थ्य मामलों पर ध्यान देने के लिए अधिक योग्य पेशेवरों का उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार मानसिक स्वास्थ्य संबंधी खर्चों को चिकित्सा बीमा के दायरे में रखने पर विचार कर रहा है ताकि रोगियों पर बोझ कम हो सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) लांगीट्यूडीनल एजिंग स्टडी इन इंडिया (एलएएसआई) रिपोर्ट के अनुसार, भारत में वृद्धजनों का एक महत्वपूर्ण अनुपात संभावित गंभीर अवसाद से ग्रस्त है।

(ख) एलएएसआई में, सेन्टर फॉर एपीडेमियोलॉजीकल स्टडीज डिप्रेशन (सीईएस-डी) स्केल का प्रयोग अवसाद के लक्षणों की पहचान करने, और कम्पोसिट इन्टरनेशनल डाइग्नोस्टिक इन्टरव्यू शोट फॉर्म (सीआईडीआई-एसएफ) स्केल, जो एक संरचित साक्षात्कार स्केल है,

का प्रयोग संभावित मुख्या अवसाद के निदान हेतु किया गया। भारत में 45 वर्ष की आयु के व्यस्क तथा इससे अधिक आयु के व्यक्तियों में सीईएस-डी स्केल की जांच में 28% में अवसाद के लक्षण पाए गए तथा 45-59 वर्ष की आयु के 26% व्यस्कों की तुलना में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के 30% व्यक्तियों में अवसाद के लक्षण पाए गए।

भारत में 45 वर्ष तथा इससे अधिक आयु के व्यक्तियों में संभावित गंभीर अवसाद की व्याप्तता दर 8% (सीआईडीआई-एसएफ के आधार पर) है। 60 वर्ष की आयु तथा इससे अधिक आयु के व्यक्तियों में संभावित गहन अवसाद की व्याप्तता (8.3%) है नैदानिक अवसाद की स्वयं रिपोर्ट की गई व्याप्तता दर (0.8%) से 10 गुणा अधिक है तथा यह स्पष्ट तौर से गैर-नैदानिक अवसाद की अधिक भार है। सीईएस-डी तथा सीआईडीआई-एसएफ परिणामों की तुलना से स्पष्ट है कि भारत में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के एक-तिहाई व्यक्तियों में अवसाद के लक्षण हैं जबकि 60 वर्ष की आयु तथा इससे अधिक आयु के प्रत्येक बारहवें व्यक्ति में संभावित गंभीर अवसाद के लक्षण व्याप्त हैं।

60 वर्ष तथा इससे अधिक आयु के व्यक्तियों में पुरुषों (7%) की तुलना में महिलाओं (9%) में संभावित गंभीर अवसाद की व्याप्तता अधिक है तथा शहरी क्षेत्र (6%) की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र (9%), विधवाओं में (10%), अकेले रहने वालों में (13%), अनुसूचित जाति में (13%) तथा जो पहले कार्य करते थे और अब नहीं करते, उनमें (10%) अवसाद के लक्षण पाए गए हैं।

(ग) : मानसिक विकारों के भार से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। सरकार निर्म्मा लिखित उद्देश्यों से देश के 692 जिलों में एनएमएचपी के तहत जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) के कार्यान्वयन का समर्थन कर रहा है:

i) आत्महत्या रोकथाम सेवाएं, कार्यस्थल में तनाव प्रबंधन, जीवन कौशल प्रशिक्षण तथा विद्यालयों और कॉलेजों में परामर्श प्रदान करना।

ii) जिला स्वास्थ्य परिचया प्रदानगी प्रणाली के विभिन्न स्तरों पर रोकथाम, संवर्धन और लंबे समय तक सतत परिचया सहित मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना।

iii) मानसिक स्वास्थ्य परिचया के लिए उपकरण, और अवसंरचना मानव संसाधन के संबंध म संस्थागत क्षमता म वृद्धि करना।

iv) मानसिक स्वास्थ्य परिचया सेवा प्रदानगी म सामुदायिक जागरूकता तथा भागीदारा को बढ़ावा देना।

(घ) मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र म योग्य जनशक्ति का उपलब्धता म वृद्धि के मद्देनजर सरकार, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) के अंतगत सटर ऑफ एक्सीलस का स्थापना करने और मानसिक स्वास्थ्य विशेषताओं म स्नातकोत्तर (पीजी) विभागा के सुदृढ़करण/ स्थापना करने के लिए जनशक्ति विकास योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। आज तक, देश म चार मानसिक स्वास्थ्य विशेषताओं नामतः (i) मनोस्थिति, (ii) क्लिनिकल मनोरोग विज्ञान, (iii) मनोरोग नर्सिंग, (iv) मनोरोग सामाजिक कायकलाप म 25 सटस ऑफ एक्सीलस और 47 स्नातकोत्तर (पीजी) विभागा के सुदृढ़करण/ स्थापना के लिए सहायता प्रदान का गई है।

सरकार, तीन कद्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थाना अथात राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं न्यूरो विज्ञान संस्थान, बगलुरु; लोकोप्रिय गोपीनाथ बोर्दालोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर, असम तथा कद्रीय मनोरोग संस्थान, रांची म स्थापित डिजिटल अकादमिया के जरिए सामान्य स्वास्थ्य परिचया चिकित्सा तथा परा-चिकित्सा चिकित्सका का विभिन्न श्रेणया के ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान कर के देश के अल्पसेवित क्षेत्रों म मानसिक स्वास्थ्य परिचया सेवाएं देने के लिए भी जनशक्ति का उपलब्धता म वृद्धि कर रहा है।

(ड.) मानसिक स्वास्थ्य परिचया अधिनियम, 2017 का धारा 21(4) के अनुसार, प्रत्येक बीमाकता मानसिक रोग के उपचार हेतु चिकित्सा बीमा म उसी प्रकार के प्रावधान करेगा जैसे कि शारिरिक रोग के उपचार हेतु उपलब्ध ह। भारतीय बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण ने दिनांक 16 अगस्त, 2018 के आदेश के तहत सभी बीमा कंपनिया को मानसिक स्वास्थ्य परिचया अधिनियम, 2017 के उक्त प्रावधाना के अनुपालन के निदेश दिए ह।
